ग्रोअर्स हैं, मैनुफैक्चर्स हैं उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट न हो इसका ध्यान रखते हुए हम, जो आयात होता है वह करते हैं।

सर, एक बात और भी बताऊंगा कि जो स्मगलिंग पहले होती थी वह अब नहीं होती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज जो सरकारी नीति अपनायी है इसके कारण स्मगलिंग बहुत कम हो गयी है और यह भी मैं मानूंगा कि अब स्मग्लिंग होने की कोई संभावना नहीं है।

MR. CHAIRMAN: We have spent half-an-hour on this question.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, this is very important subject. ... *(interruptions)* ... I request that Half-an-hour Discussion may be allowed on this subject.

MR. CHAIRMAN: All right.

Rural Development Projects

*42. SHRI MOOLCHAND MEENA+:

SHRI NANA DESHMUKH:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Minister has expressed displeasure at the slow implementation of rural projects by States despite adequate allocation of funds by the Union Government;

(b) if so, whether after a review focusing on the Southern States, the Minister found that despite a positive response from several States to the Centre's plea for more transparency, the situation at the village level continues to be unsatisfactory;

(c) if so, which are the States where there has been slow progress in rural projects; and

(d) what are the suggestions made by the Union Government to the States to implement the rural development schemes vigorously?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

+ The question was actually asked on the floor of the House by Shri Moolchand Meena.

Statement

The Minister of Rural Development has been regularly reviewing the performance of different States and Union Territories in respect of various Programmes of the Ministry with a-view to improving performance at the grass roots level. As part of these reviews, it has been found that some States/Districts have not been able to avail full Central allocations under one or more Rural Development Programmes and that even as several States are responding positively to the need to accelerate and improve implementation, the situation at the village level is yet to fully reflect the same.

It has been urged upon the States/UTs to interact with the Ministry at regular intervals so as to ensure that the funds for different Programmes are duly claimed and expenditure incurred in time. Emphasis is also laid on the quality of implementation of the Programmes. The States/UTs have been advised to urgently implement the Four Point Strategy of Creating Awareness about the Programmes, Transparency, Peoples' Participation and Accountability through Social Audit by the Gram Sabhas, for the benefit of the rural masses. Submission of requisite proposals by the States and Union Territories for release of Second Instalment before the end of February would afford sufficient time to utilize the funds in the same financial year.

The position of release of funds in the current year (upto 30th June, 2002) taken as an indicator of performance, shows that among the Southern States. Tamil Nadu has been able to obtain the First Instalment of funds under all allocation based Programmes during the current year; Karnataka could not obtain the First Instalment for 8 Districts under the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) and for 4 Districts under DRDA Administration. The State of Kerala could not obtain the First Instalment under the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) (Stream-I) for 2 Districts and, under the Indira Awaas Yojana (IAY), for 3 Districts; Andhra Pradesh could not obtain the First Instalment under the IAY for 7 Districts.

श्री मूल चन्द मीणा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास योजनाओं पर चालू वर्ष में राज्यों को कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है और किस मापदण्ड के आधार पर, इसका राज्यवार विवरण बताएं ? दूसरा, ग्रामीण विकास योजनाओं पर इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी गांवों का विकास नहीं हो पाता है। राजीव गांधी ने कहा था कि

गांवों के विकास के लिए सरकारी खर्च एक रुपया आता है तो गांवों तक पहुंचने पर वह 25 पैसे रह जाता हैं.... (**व्यवधान**) 15 पैसे रह जाता है। यह व्याप्त भ्रष्टाचार आज भी कायम है। उसको रोकने के लिए सरकार .... (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने शुरू कर दिया था.... (**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द मीणा : राजीव गांधी ने तो साफ कहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये उसको छिपाना चाहते हैं। तो भष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ? मेरा ''सी'' पार्ट है—क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु बनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है, यदि किए गए हैं तो पिछले तीन सालों में उन लक्ष्यों पर क्या कार्यवाही पूरी हुई या नहीं, यह बताएं ?

श्री शांता कुमार : महोदय, पहला प्रश्न पूछा है कि इस वर्ष कितना आवंटन हमारी ओर से किया गया 2002-03 के अंदर कुल मिलाकर योजनाओं के अंदर 38 प्रतिशत जो हमको आवंटन करना था - 5639 करोड़ रुपए में से हमारी रिलीज 2160 करोड़ रुपए है अर्थात इस वर्ष के प्रारंभ में जो पहली किश्त है वह लगभग हम सबको दे चुके हैं। दूसरी किश्त की ज्योही डिमांड आएगी हम दे देंगे।

दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है उसमें यह सत्यता है कि जितना धन आवंटन भारत सरकार की तरफ से हाता है उस धन का पूरी युटिलाइजेशन राज्यों के अंदर नहीं हो पा रहा है। 2001-02 के अंदर हमको 7861 करोड़ रुपए का आवंटन करना था। इसमें से केन्द्र सरकार ने 7784 करोड़ अर्थात हमारी तरफ से 99.02 परसेंट आवंटन तो 2001-02 में हो गया है। इस वर्ष का हमारा आवंटन तीन-चार महीनों का जो है वह 38 परसेंट है। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा उस बात में सच्चाई है कि अभी भी जो टोटल अवेलेबुल फंड्स विभिन्न राज्यों के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास हैं वह कुल मिला कर 20 हजार करोड़ रुपया था पिछला भी और पिछले वर्ष का भी, जो हमने दिया। उस बीस हजार करोड़ रुपये में से जो एकच्युअल यूटिलाइजेशन है वह 10,429 करोड़ रुपये है अर्थात जो टोटल अवेलेबल फंड्ज ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध थे उनमें जो एक्च्युअल यूटिलाइजेशन है वह केवल 51.94 प्रतिशत है। आपने लक्ष्य पूछा है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि 50 प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि उनको पूरा करने में नहीं हुई है। इस संबंध में विभाग में और विशेषकर पूर्ववर्ती मंत्री श्री वेंकैया नायडु जी ने राज्य स्तर पर मुख्य मंत्रियों से और बाकियों से विशेष विचार-विमर्श कर के एक निश्चित प्रक्रिया बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस पैसे का ठीक उपयोग हो सके। उसके लिए मॉनिटरिंग और विजिलेंस कमेटी जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर बनाने के निर्देश

राज्य सरकारों को दिए हैं। यदि वे विजिलेंस कमेटीज प्रत्येक स्तर पर बन जाएं और अपने-अपने स्तर पर सारे खर्च को ठीक ढंग से करने का निर्णय करें तो उपलब्धि भी हो सकती है और लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मेरी सैकंड सप्लीमेंटरी यह है कि ग्रामीण विकास योजनाओं को रोज़गार परत बनाने की सरकार की नीति है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत अभी तक देश में कितने स्वसहायता समूहों का सृजन किया गया है तथा सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना को प्रभावी और उत्पादनकारी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, किस-किस प्रदेश में, किस-किस योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त हो गया और कितना धन उन्होंने ले लिया। यह पूरी सूचना मेरे पास है। यदि आप कहें तो मैं वह सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री सभापति : हां रख दीजिए।

श्री शांता कुमार : प्रत्येक प्रदेश की प्रत्येक योजना का पूरा ब्यौरा मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि इस ब्यौरे को माननीय सदस्य अवश्य देखें कि उनके प्रदेशों की इन योजनाओं के बारे में क्या स्थिति है। यदि आप चाहें तो वह ब्यौरा मैं आपको दे सकता हूँ और सदन के पटल पर रख सकता हूँ ताकि पूरी जानकारी आपके पास आए।

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU : Sir, the hon. Minister has mentioned in his reply, 'The States and Union Territories have been advised to implement the four-point strategy of creating awareness about the programmes, transparency, peoples' participation and accountability through social audit by the Gram Sabhas. Conducting of elections for Panchayats is a Constitutional obligation. My supplementary is this. The hon. Home Minister is also sitting here. Sir, for the last thirty-five years, the Panchayat elections have not been conducted in the Union Territory of Pondicherry. Many Governments have come and gone. Many promises have been made. My submission to the hon. Minister is, unless the Ministry refuses to release funds to the Union Territory of Pondicherry, the Government in Pondicherry will not conduct elections. What I suggest to the hon. Minister is that he should give a direction to the Government of Pondicherry to conduct Panchayat elections there failing which the funds would not be released. The hon. Home Minister may also kindly take note of this fact. Sir, the Panchayat elections have not been conducted inspite of a large number of agitation by different political parties.

श्री शांता कुमार : मान्यवर हमने उनको अति शीघ्र चुनाव कराने की बात कही है लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पंचायतों द्वारा सोशल आडिट हो, जहां पंचायतें नहीं हैं, वहां ग्राम स्तर पर विजिलेंस कमेटी बने और वह काम करे, जो पंचायतों को करना चाहिए, यह भी निर्देश दिया है लेकिन पंचायतों का चुनाव जल्दी कराने के लिए भी उनको कहा गया है।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Sir, my suggestion was that the hon. Minister should give a direction to the Government of Pondicherry to conduct Panchayat elections. My main supplementary is whether a direction can be issued by the Central Government to the Government of Pondicherry under the Constitution for conducting Panchayat elections. That is my question. My pertinent question is : Are you going to issue a direction to the Government of Pondicherry to conduct Panchayat elections there? You tell them categorically that otherwise the funds would not be released.

श्री शांता कुमार : हमने उन्हें सलाह दी है और आगे भी हम उनको सुझाव देंगे कि वे जल्दी-से-जल्दी चुनाव कर लें।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Sir, we all know the Ministry of Rural Development plays a very important role in helping the poor people. You are getting thousands of crores of rupees for helping the people at the grass root level in the rural areas all over the country. Former Union Rural Development Minister, Shri M. Venkaiah Naidu, said that the Ministry was unhappy with the slow progress of rural projects. He, in another statement, also said that the States lacked the will to implement rural development schemes. It has been mentioned that due to various problems, like Utilisation Certificates not coming, audit reports not coming from the States, you have not been in a position to release funds. So, this is happening. Mr. Venkaiah had announced that he was planning to have a conference in the first week of July, perhaps on July 5th or 6th, at Hyderabad, of the Directors of District Rural Development Agencies and Chief Executive Officers of Zila Parishads. I would like to know whether this conference took place or not. The idea, he was mentioning, was of getting 600 delegates from all over the country to inspire them to act and give information from all States, and see that funds are released immediately. If the conference took place, what had been its outcome? If the conference has not taken place, when are you going to hold this conference? What steps are you going to take to make the State Governments provide information? Since some States have

not provided the information, you have not been able to release the funds. Of course, technically you are correct. But merely saying that since the State Governments have not provided information, you have not been able to give funds is not correct. You are, thus, making the poor people suffer. It is the duty of the Central Government to pin down the State Governments and give them a time limit to provide information. If even then they do not provide information you tell them to forget about the funds and say that you would divert those funds to some one else. So, what steps are you going to take in this regard? And, if that Conference has not taken place, when is it going to take place?

श्री शांता कुमार : सभापति महोदय, जैसा कि आप ने कहा, नियम यह है कि वर्ष के प्रारंभ में पहली किस्त विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदेशों को दे दी जाती है। उसके बाद जब प्रदेशों से यह ब्यौरा आता है कि कुल उपलब्ध राशि का कम-से-कम 60 प्रतिशत खर्च कर लिया गया है तो फिर दूसरी किस्त रिलीज हो जाती है। सभापति महोदय, अधिकतर दूसरी किस्त इसलिए रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि कुल उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट यहां समय पर नहीं आ पा रहा है। माननीय सदस्य ने हैदराबाद कांफरेंस के बारे में पूछा। हैदराबाद कांफरेंस तय थी और माननीय प्रधान मंत्री जी वहां जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण वह कांफरेंस पोस्टपोन हो गयी। इस बारे में मेरी मान्यवर प्रधान मंत्री जी से बात हुई है और बहुत जल्द हैदराबाद में ही वह कांफरेंस होने वाली है। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा निश्चित रूप से इतने धन का प्रावधान देश के गांवों के लिए, गरीबों के लिए, पानी, सड़कों, हाउसिंग के लिए और गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप ने कहा कि यह केन्द्र की ड्यूटी है। यह केन्द्र और राज्य दोनों की ड्यूटी है और अधिकतर हमारे जिम्मे पहला काम यह है कि धन का प्रावधान करें। अब धन का प्रावधान कर दिया, 99 परसेंट रिलीज भी कर दिया है, लेकिन धन तो राज्यों के पास है और उसका केवल 51 परसेंट यूटिलाइजेशन हुआ है। यह विचार करने वाली बात है। महोदय, मैं चाहूंगा कि मान्यवर सदस्य सुझाव दें कि इस धन का यूटिलाइजेशन किस ढंग से अधिक बढ़ाया जा सकता है। महोदय, योजना है कि ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर कमेटीज बनें। उनमें पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स को एसोसिएट किया जाए, वह देखें कि धन का खर्च हो रहा है या नहीं और उसे ठीक ढंग से खर्च करें। इस तरह यदि सचमुच में ये सारी कमेटीज बनकर अपने-अपने स्थान पर अपना काम करना शुरू कर दें तो फिर यूटिलाइजेशन कम नहीं होगा। सभापति महोदय, इस संबंध में श्री वेंकैया नायडू जी ने एक-एक विषय का विचार किया है। मैं भी एक-एक विषय का रिव्यु कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बारे में सुझाव दें। मैं सहमत हूं कि यूटिलाइजेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। सचमुच में यह धन वहां खर्च हो, उस के लिए जो

कुछ भी किया जाना है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप के जो भी सुझाव होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार को इस आधार पर 600 करोड़ रुपया रिलीज नहीं किया गया था कि बिहार में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब बिहार में पंचायतों के जिला परिषदों के सारे चुनाव पूरे कर लिए गए हैं, तो उसके बाद भी बिहार के साथ इतना अन्याय और भेदभाव क्यों हो रहा है ? यह 600 करोड़ रुपया रिलीज न करने का कौनसा औचित्य है ? माननीय, आपके पहले जो मंत्री जी थे, उनके द्वारा प्रधान मंत्री सड़क योजना सब राज्यों को क्लीयर कर दी गई और आपने यह स्वीकार किया कि पंचायतों के, जिला परिषद् के, प्रखंड के चुनाव होने पर नीचे के ग्रास रूट के लेवल पर योजनाओं का चयन करेंगे, यही डेमोक्रेसी का तकाजा भी है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि माननीय मंत्री ने एन०डी०ए० के एम०पीज० के दबाव में बिहार की प्रधान मंत्री सड़क योजना को रोक कर रखा और जिसकी वजह से वहां काम आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है ? इसका साफ-साफ जवाब हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

श्री शांता कुमार : मान्यवर, जो नियम इस योजना में हैं, वे पूरे प्रदेशों में बराबर लागू किए जाते हैं। मेरे पास बिहार का पूरा ब्यौरा है कि किस योजना में कौन सी किस्त रिलीज कर दी गई है और किस योजना में किस्त रिलीज नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है।...**(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसाद : बिहार में पंचायत के चुनाव न होने की वजह से आपने कहा कि हम बिहार को पैसा नहीं देंगे। जब यह चुनाव हो गए हैं तो हमारा पैसा आपने क्यों रोक रखा है, जबकि बार-बार वहां की सरकार, वहां के मुख्य मंत्री, सभी पोलिटिकल पार्टी के लोग आपको बोलते रहे हैं ? बिहार के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

श्री शांता कुमार : सर, कोई पैसा नहीं रोका गया है। ज्यों ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके मुताबिक पैसा रिलीज कर दिया जाता है। किसी के दबाव में किसी प्रदेश का कोई पैसा रोकने का सवाल पैदा नहीं होता। इस तरह किसी प्रदेश का कोई पैसा नहीं रोका गया है।...**(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसाद : महोदय, he is misleading the House, मेरा प्रश्न यह है कि 600 करोड़ रुपया, जो बिहार को गांव विकास योजना में पंचायतों के द्वारा काम करने के लिए मिलना था, वह पैसा पंचायत चुनाव न होने का कारण बताकर नहीं दिया गया और आप जवाब दे रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। आप हसुवा की बात कर रहे हैं और हम खुरपी का गीत गा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

SHRI JIBON ROY : An assurance was given in the House that when elections take place, all the money would be released.

श्री शांता कुमार : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर...(**व्यवधान**)... the first instalment was released to 25 districts. And, the first instalment could not be released to 12 districts due to non-submission of the Revised Audit Report and the Utilization Certificate for the year 2002.

श्री लालू प्रसाद : सर, आप क्या जवाब दे रहे हैं ? ...(**व्यवधान**)

श्री शांता कुमार : सभापति जी, ज्योंही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, पैसा रिलीज हो जाएगा।...(**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं, मैं प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)

श्री जीवन राय : जो 600 करोड़ रुपया पंचायत चुनाव के बाद बिहार को देने का था, उसका क्या हुआ ? ...(**व्यवधान**)

श्री शांता कुमार : जहां तक पंचायत फंड का सवाल है, यह एक अलग सवाल है और यह फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज किया जाता है।...(**व्यवधान**)

श्री दीपांकर मुखर्जी : स्टेट का बटवारा करा दिया। क्या झारखंड में स्कीम का पैसा चला गया ? बिहार को क्यों नहीं मिला ?...(**व्यवधान**)

श्री जीवन राय : क्या आप बिहार को उसका 600 करोड़ रुपया नहीं देंगे ? ...(**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। ... (**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद : चुनाव हो गए, लेकिन वह पैसा नहीं दिया गया और बिहार को बांटा और अब ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बात कहते हैं। ... (**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु : सर पंचायत के चुनाव न होने के कारण जो पैसा रोका हुआ था ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Let him reply...*(Interruptions)*...Let him reply...*(Interruptions)*...Let him reply...*(Interruptions)*...

श्री शांता कुमार : महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि इन सब योजनाओं के अंदर एक नियम है जिस नियम के मुताबिक धन का प्रावधान किया जाता है, जो-जो राज्य सरकारें यूटिलाइजेशन

सर्टिफिकेट, आडिट रिपोर्ट इन नियमों का पालन करती है, उनको पैसा रिलीज कर दिया जाता है, यदि उसका पालन नहीं होता तो पैसा रिलीज नहीं होता। ... (**व्यवधान**) ...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, ये गलत जवाब दे रहे हैं। हमारी जो ड्यू मनी है, वह क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं ? ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply...*(Interruptions)*... Let the Minister reply ... *(Interruptions)*... Let the Minister reply ... *(Interruptions)* ...

श्री एस० एस० अहलुवालिया : सभापति जी, जवाब तो सुना जाए। ... (**व्यवधान**) जवाब तो सुना जाना चाहिए। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply...*(Interruptions)*... Let him reply... *(Interruptions)*.

प्रो. रामगोपाल यादव : सर, सवाल यह है कि जब पैसा दिया ही नहीं तो यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट कैसे आ जाएगा। ... (**व्यवधान**) जब पैसा ही नहीं दिया तो यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट कहां से आएगा। ... (**व्यवधान**) ...

श्री एस० एस० अहलुवालिया : जवाब तो सुना जाना चाहिए। ... (**व्यवधान**) ...

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी तैयार होकर नहीं आए जवाब कौन सुनेगा। ... (**व्यवधान**) .....

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, निर्देशन दिया जाए कि मंत्री जी तैयारी करके आया करें, मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply.

श्री सुरेश पचौरी : प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है, मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए हैं। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply. मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री शांता कुमार : महोदय, जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूरे देश में जो प्रावधान हमने किया है, उसका 51 परसैंट युटिलाइजेशन हुआ है। मैं बिहार का बता रहा हूं कि बिहार को कुल योजना में 1412 करोड़ देना था, 731 करोड़ दिया जा चुका है जो 51.82 परसैंट बनता है। पूरे देश में अभी 51 परसैंट दिया और बिहार को 51.82 परसैंट दिया है।... (**व्यवधान**) ...

श्री लालू प्रसाद : ये गलत पढ़ा रहे हैं इनको ...(**व्यवधान**) यह कोई दूसरा पढ़ रहे हैं। ...(**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**) ... आप बैठिए, आप भी बैठिए। ...(**व्यवधान**) ... एक मिनट, प्लीज। Mr. Minister, the Hon. Member has put a specific question about releasing of Rs. 600 crores. That is the point. If you can clarify it please clarify it... *(Interruptions)* ...

श्री शांता कुमार : प्रधान मंत्री जी ग्राम सड़क योजना में बिहार को 149.90 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और अभी हाल ही में 298 करोड़ रुपये का कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir ... *(Interruptions)* ...

श्री शांता कुमार : 298 करोड़ रुपये का कार्यक्रम अनुमोदित किया जा चुका है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, the Hon Member wanted to know whether some money was withheld because of non-holding of the Panchayat elections. The Hon. Member's point was that, Rs. 600 crores were withheld. The question is simple. The question is, whether any amount was withheld because of non-holding of the Panchayat elections, and, if so, what is the amount? Let him answer that question.

श्री शांता कुमार : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 298 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अनुमोदन दिया जा चुका है ... (**व्यवधान**)

श्री लालू प्रसाद : सर, ये हाऊस को गुमराह कर रहे हैं। ... (**व्यवधान**) जब पंचायत का चुनाव बिहार में हुआ था तो वहां का काफी रुपया रोका गया। ये सही नहीं कह रहे हैं। ... (**व्यवधान**)

SHRI NILOTPAL BASU : Sir, he is refusing to reply to the specific question. The question is, whether any money was withheld for non holding of the Panchayat elections in Bihar ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply ... *(Interruptions)* ...

SHRI SHANTA KUMAR : Sir, the previous funds of the Tenth Finance Commission have lapsed ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Let him reply ... *(Interruptions)* ...

SHRI SHANTA KUMAR : The funds of the Eleventh Finance Commission would be released after the Panchayat elections are completed ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Let him complete ... *(Interruptions)* ...

श्री शांता कुमार : दसवें फाइनेंस कमीशन में जो प्रावधान था पंचायत चुनाव न होने के कारण वह तो लेप्स हो गया था। ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन का जो प्रावधान है वह पंचायत चुनाव की कम्प्लीशन की सारी फार्मिलिटीज के बाद दिया जाएगा। जहां तक ग्रामीण सड़क का मामला है मैंने कहा कि ... **(व्यवधान)**

SHRI J. CHITHARANJAN :The Minister has replied several times. But he is not answering the question. He should answer the question ... *(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : हमारा चुनाव हो गया है तो पैसा रिलीज करें ... **(व्यवधान) ...**

श्री नीलोत्पल बसु : इस लिए नहीं दिया गया कि बिहार सरकार आपके साथ नहीं है। अब बताएं कि कब तक दिया जाएगा। ... **(व्यवधान) ...**

MR. CHAIRMAN : Let him reply.

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी के वक्तव्य में खुद विरोधाभास है। यह कह रहे हैं कि ... **(व्यवधान) ...**

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply ... *(Interruptions)* ...

SHRI JIBON ROY : We want an assurance ... *(Interruptions)* ...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR : I strongly object to what Shri Laluji has said. Please do not take the name of our Chief Minister ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply ... *(Interruptions)* ... Let him reply ... *(Interruptions)* ...

श्री लालू प्रसाद : मंत्री जी बताएं कि यह पैसा देंगे या नहीं देंगे। हम आपकी सरकार के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे ... **(व्यवधान) ...**

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : He must tell the House ... *(Interruptions)* ...

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी का जवाब नहीं आया ... **(व्यवधान) ...**

SHRI JIBON ROY : We want an assurance from the Government ...

(Interruptions) ... No money has been given to Bihar ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over ... *(Interruptions)* ...

श्री लालू प्रसाद : क्या आप बिहार के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं ? बिहार में इनकी सरकार दिल्ली से चल रही है। आपने बिहार को 670 लाख रुपया नहीं दिया है। आप बता रहे हैं कि हम देंगे। आप यह धनराशि कब देंगे ? आप इसको कब रिलीज करेंगे ? ... (**व्यवधान**) ...

श्री शांता कुमार : पैसा दिया जा चुका है। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over now. Papers to be laid on the Table ... *(Interruptions)* ...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, we would like to know from the Minister whether the money has been given to Bihar or not. The Minister must answer this question. ... *(Interruptions)* ...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति महोदय, इस विभाग में जो मंत्री आते हैं। ... (**व्यवधान**) ... इस विभाग में रहे हुए मंत्री एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। इस विभाग को इन्होंने ऐसे समझ लिया है कि इस विभाग में आने पर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन जायेंगे।.....(**व्यवधान**)...

SHRI JIBON ROY : Sir, Shri Advaniji had assured this House that the money would be given to Bihar ...*(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Question hour is over now. Papers to be laid on the Table ... *(Interruptions)* ...

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, इनको डायरेकशन दिया जाए कि ये हमारी बिहार स्टेट को पैसा रिलीज करें...(**व्यवधान**). . . . केन्द्र सरकार 600 करोड़ रुपया रिलीज करे। बिहार का बंटवारा करते समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि हम बिहार को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अब हमारे यहां पंचायत के चुनाव हो गये हैं।...(व्यवधान). . . . आपने बिहार का छह सौ करोड़ रुपया रोक रखा है। आप इसको कब रिलीज कर रहे हैं, इसके बारे में बताइये। ...(**व्यवधान**) ...

श्री विक्रम वर्मा: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जबाब दे रहें हैं, लेकिन माननीय सदस्य सुनने को तैयार नहीं हैं...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : There must be assurance from the Minister or the Deputy Prime Minister that the money will be given to Bihar ... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : The Minister wants to say something Please sit down. ... *(Interruptions)* .....

श्री शांता कुमार : सभापति महोदय, विभिन्न योजनाओं में जो पैसा दिया गया है। उसके बारे में मैंने बताया है। हम उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने पर देखेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, जब पैसा दिया ही नहीं है तो यूटिलाइजेशन का प्रश्न कहां आता है ... (**व्यवधान**) ... अभी तो पैसा ही रिलीज़ नहीं किया है। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over ... *(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, the question has not been answered. Rs. 600 crores must be given to Bihar. We want an assurance from the Minister ... *(Interruptions)* ...

श्री जीवन राय : जब रुपया ही नही तो दिया है । उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ? ... (**व्यवधान**) ...

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी ने बताया है कि 298 करोड़ रुपया दिया जा चुका है ...(**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over ...*(Interruptions)*... You can raise this issue through Half-an-Hour discussion ...*(Interruptions)* ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, the Minister has stated that he will be giving the money to Bihar. When will he give the money? ...*(Interruptions)*...

श्री दीपांकर मुखर्जी : पैसा कब देंगे, यह बताइए।...(**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up the next business ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रम वर्मा : इसके लिए नोटिस दें। ऐसा कैसे हो सकता है ? ... (**व्यवधान**) ...

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला : यह हाउस का समय बर्बाद करे रहे हैं ... (**व्यवधान**) ...

SHRI JOBON ROY : This is the Council of States ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over ...*(Interruptions)*... We will now go to the next busines... *(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, when is he going to release the money?...*(Interruptions)*... they can't withhold the money because of non-holding of panchayat elections. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can give notice for a Half-an-hour Discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: This is not fair, Sir. ...*(Interruptions)*...

प्रो० रामदेव भंडारी : इसमें हाफ ऐन ऑवर डिसकशन की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया है ? ... **(व्यवधान) ...**

श्रीमती सरोज दुबे : सीधी सी बात है, पैसा क्यों नहीं दिया गया है ? **...(व्यवधान) ...**

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over. ...*(Interruptions)*... Please sit down ... *(Interruptions)*... We are going to the next business ...*(Interruptions)*... Papers to be laid on the Table, Shri L.K. Advani ...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : हम सदन से वाक आउट करते हैं। ... **(व्यवधान)...**

श्रीमती सरोज दुबे : ये बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे मे मानते ही नहीं हैं, इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

[*At this stage some hon. Members left the Chamber.*]

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table, Shri L.K. Advani ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: This is the Council of States. ..... *(Interruptions)*... You cannot deprive any state of its share ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we are also walking out ...*(Interruptions)*...

[*At this stage some hon. Members left the Chamber*]

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MANMOHAN SINGH): Sir, we are also walking out ...*(Interruptions)*...

[*At this stage some hon. Members left the Chamber.*]

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

[WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS]

Special Bulldozers for Border Fencing

*43. SHRI YADLAPATI VENKAT RAO : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Boarder Security Force engaged in the work of fencing along International border in Jammu and Kashmir to prevent infiltration have asked for supply of special bulldozers;

(b) if so, whether it is a fact that in the face of continuous Pakistani firing from across the border, special types of bulldozers are necessary for carrying out digging, levelling and building of bunds; and